कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

"शांति, सुरक्षा और सद्भाव' के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तीन दिनों का 'सद्भावना' उपवास अहमदाबाद में 17, 18 एवं 19 सितम्बर 2011 को सम्पन्न हुआ।"

गुजरात : 'सद्भावना मिशन'
एक रिपोर्ट 6

लेख
'व्हिसल–ब्लोअर' जेल नहीं, अभिनन्दन के पात्र
&ykyÑ".k vkMok.kh 21
अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बना मध्य प्रदेश
&eukt dekj JhokLro 23

अन्य
भाजपा किसान मोर्चा : जयपुर (राजस्थान) 11
भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 13
हरियाणा : भाजपा–हजकां का हुआ गठबंधन 14
उत्तराखंड : भुवन चंद्र खंडूरी बने मुख्यमंत्री 25
मध्य प्रदेश : भाजपा ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन 26
दिल्ली : रक्तदान शिविर का आयोजन 28

प्रदेशों से
हिमाचल प्रदेश 22
राजस्थान 27
उत्तर प्रदेश 30
झारखण्ड 30

बोध कथा

लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था....

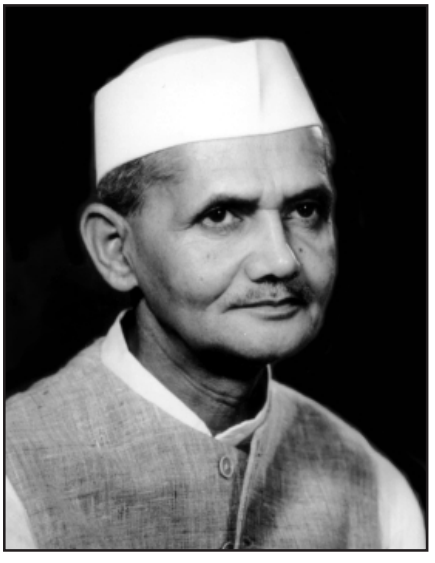

मैं पाकिस्तान के लोगों को कह देना चाहता हूं कि ये धोती वाला प्रधानमंत्री टहलते–टहलते हुए लाहौर की धरती पर पहुंचेगा। ऐसा बड़ा उत्साह के साथ भाषण दिया था उन्होंने। भारत की फौजों ने बड़ा पराक्रम किया और अपना पुराना क्षेत्र प्राप्त कर लिया, तो भारत की विजय दुनिया के बड़े देशों को रंज देती थी। अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव डाला 'सीज फायर' करो, तो लालबहादुर शास्त्री ने कहा– हम आपके कहने से नहीं करने वाले। इस बारे में हम सोचेंगे। भारत का कैबिनेट सोचेगा। तुम हमें डिक्टेट करने वाले कौन होते हो? ऐसा अमेरिका को लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अमेरिका को भारत का प्रधानमंत्री ऐसा कहने की हिम्मत करता है। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है, जो हमारे दानों पर पलता है वो देश कुछ कहे? अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को, अर्थ क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय अमेरिका का गेहूं से लदा हुआ जहाज भारत के लिए रवाना हो चुका था। दबाव–डालने के लिए वह जहाज हिन्द महासागर में रोक दिया और कहा 'हमारे गेहूं पर पलने वाला देश हमारी बात नहीं मानता, गेहूं नहीं भेजेंगे। ऐसा उन्होंने गेहूं के माध्यम से दबाव डालने का प्रयत्न किया। लाल बहादुर शास्त्री स्वाभिमानी प्रधानमंत्री थे। देश के स्वातंत्र्य व स्वाभिमान के साथ सौदा नहीं कर सकते थे। तो लालबहादुर शास्त्री ने आह्वान किया, देशवासियों को 'हम भूखे रहेंगे पर स्वाभिमान का सौदा नहीं करेंगे' मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि सप्ताह में एक दिन सोमवार को व्रत रखें। याद होगा, सोमवार का व्रत प्रारम्भ हो गया था। हमने फूड ग्रेन बचाया और स्वाभिमान का सौदा नहीं किया।

व्यंग्य चित्र

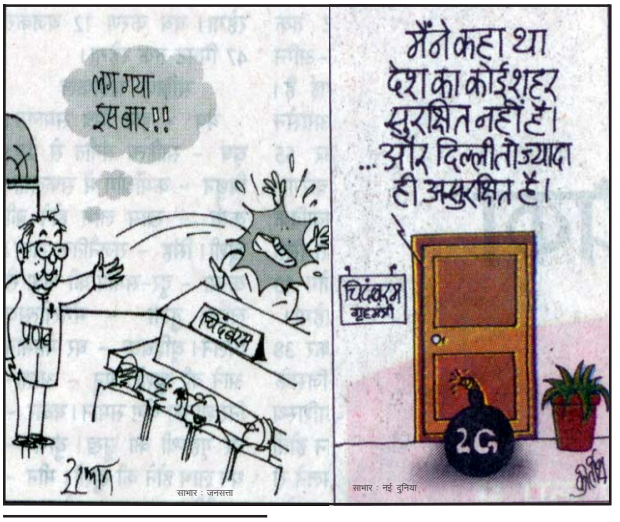

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सम्पादकीय

क्या अब तिहाड़ में होगी मंत्रिमंडल की बैठक!

देश का सिर शर्म से झुक रहा है, पर कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार का सिर नहीं झुक रहा। एक ने कहा कि सिर तब झुके जब सिर हो। सच में वर्तमान कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार पूरी तरह भानुमति का कुनबा है और वह अब-बिखरने के कगार पर है। समाचार पत्रों और दृश्य मीडिया के अधिकतर चैनलों पर एक ही खबर चल रही है कि अब सिर्फ डॉ. मनमोहन सिंह ही बचे हैं। आखिर! क्या देश को ये दिन देखने पड़ेंगे? क्या इसी का नाम केन्द्रीय सरकार है? देश समझ नहीं पा रहा है। तिहाड़ की लाइन में देश का गृहमंत्री! सभी स्तब्ध हैं।

हालात की गम्भीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह एक मिनट में इस्तीफा दे दें। क्या कुर्सी की कीमत पर भारत को बदनाम करने का टेंडर कांग्रेस पार्टी ने भरा है? विश्व में क्या स्थिति हो रही है? मंत्रिमंडल के सदस्य तिहाड़ जेल की ''क्यू'' में लगे हैं।

'टू-जी स्पेक्ट्रम' के बारे में सारा देश जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है? क्यों नहीं, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह देश के समक्ष श्वेत पत्र जारी करते हैं? आजादी के 64 वर्ष बाद किसी ने नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि तिहाड़ जेल में केन्द्रीय मंत्रियों को जाना पड़ेगा। बच्चे-बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। जेबकतरों से लेकर अन्य अपराधी इस बात से खुश है कि चलो, जिस सरकार के इशारे पर जेल चलता है, उसी सरकार के नुमाइंदे अब उनके साथ वहां आरोपी के रूप में आ रहे हैं।

जब नेता जेल जाते थे पूरा देश गर्व करता था। आज स्थिति क्या है? देश मन्नत मांग रहा है कि सभी के सभी केन्द्रीय मंत्री जेल चले जाएं। मजेदार मामला यह है कि देश जिस सच्चाई को समझ चुका है उसे देश चलाने वाले नहीं समझ पा रहे हैं। स्थिति तो साफ हो गई है कि वर्तमान कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की साख मिट्टी में मिल चुकी है। अब उसके सामने संकट यह है कि वह मिट्टी में मिल चुकी साख को जनता में लेकर कैसे जाए?

राष्ट्रधर्म तो यही कहता है कि जिस सरकार पर से जनता की आस्था उठ जाए तो उसे एक क्षण भी सत्ता में नहीं बने रहना चाहिए पर यहां तो उल्टा हो रहा है। केन्द्र सरकार जितनी बुरी तरह घिर रही है, उतनी ही तेजी से वह एक-दूसरे को बचाने में लग गए हैं।

सवाल यहां यह है कि सरकार आएगी-जाएगी और चलेगी, पर यदि एक बार देश की साख चली गई तो उस लाने में वर्षो लग जाएंगे। जो सत्ता में आज कांग्रेस नीत यूपीए सरकार बैठी है उसे सोचना चाहिए कि देश की साख दांव पर नहीं लगे। काश! ऐसा सोच पाते? स्वार्थ की ज्वाला में इतना नहीं जलना चाहिए कि देश की अस्मिता खतरे में पड़ जाए।

समय रहते यदि उचित निर्णय केन्द्र की आरोपी सरकार ने नहीं लिया तो शायद देश जो सड़कों पर धीरे-धीरे आ रही है उसे पूरी तरह उतरना पड़ेगा। ■

मुझे और शक्ति जुटानी है, आगे बढ़ना है : नरेंद्र मोदी

'kkंति, सुरक्षा और सद्भाव' के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तीन दिनों का 'सद्भावना' उपवास अहमदाबाद में 17, 18 एवं 19 सितम्बर 2011 को सम्पन्न हुआ। गुजरात विश्वविद्यालय के एक्जिबिशन हॉल में उपवास के पहले दिन श्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात दंगों ने बहुत गहरे घाव दिए, इसके बावजूद राज्य का विकास बिना रुके जारी रहा। उन्होंने कहा कि इस सद्भावना उपवास का मकसद वोट बैंक की राजनीति का खात्मा करना है।

इस मौके पर श्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात दंगों के दौरान ऐसा माहौल बन गया था कि मुझे कोई कुछ भी सुनने, समझने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि वह मुश्किलों से भरा ऐसा दौर था जब किसी ने गुजरात का साथ नहीं दिया।

श्री मोदी ने कहा कि दंगों का दर्द समझने वाला कोई नहीं था लेकिन उनकी सरकार इससे सख्ती से निपटी। उन्होंने कहा कि गुजरात देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में सद्भावना के कई उदाहरण गिनाते हुए कहा कि साल 2002 में भूकंप त्रासदी के बाद देश–दुनिया में मान लिया गया था कि गुजरात दुबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये गुजरात का सामर्थ्य है और वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड है कि तीन साल के भीतर गुजरात न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि विकास की ओर दौड़ने लगा था।

श्री मोदी ने कहा, "मेरा सद्भावना मिशन वोट बैंक की राजनीति के अंत की शुरुआत है। बिना तुष्टिकरण किए मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूं।" उन्होंने कहा, "मेरा उपवास किसी के खिलाफ नहीं है. मैं सबका साथ और सबका विकास चाहता हूं। हमारी कोशिश यही है कि देश का हर तबका सुखी हो।"

उपवास के दूसरे दिन श्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान

इनका कहना है...

सर्वोच्च न्यायालय में आप सफलतापूर्वक अग्निपरीक्षा से गुजर चुके हैं। इस फैसले से यह साबित हो गया है कि सच की जीत होती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके खिलाफ दुष्प्रचार और झूठ की हार होगी।

& fufru xMdjh, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

(नरेन्द्र मोदी को लिखे शुभकामना पत्र में)

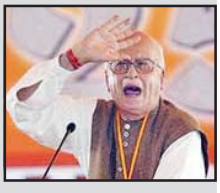

अगर आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर पूरा देश नरेन्द्र मोदी की तरह 'शून्य सहनशीलता' की नीति अपना ले तो भारत दुनिया में नई बुलंदियां छू सकता है।

& ykyÑ".k vkMok.kh, अध्यक्ष, भाजपा संसदीय दल

नरेंद्र भाई ने जो विकास गुजरात में किया है, वह पूरे राष्ट्र के लिए एक मॉडल बन चुका है। गुजरात में किसी का धर्म पूछकर उसका विकास नहीं किया गया।

&l"kek Lojkt] लोकसभा में विपक्ष की नेता

एक ओर गुजरात सरकार राज्य को 'नई ऊंचाईयों' तक ले जा रही है और दूसरी ओर केन्द्रीय स्तर पर 'भ्रष्टाचार एवं हताशा' को लेकर 'चिंताजनक स्थिति' है।

&v#.k tsVyh] राज्यसभा में विपक्ष के नेता

गुजरात की उपलब्धियां गिनवाईं। उन्होंने गुजरात को सबसे विकसित और सफल राज्य बताया। श्री मोदी ने कहा कि उनका उपवास किसी खास समुदाय या धर्म को लुभाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात को सांप्रदायिक दंगे को लेकर बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी पुरी सहानुभूति है। मैं आज भी उस घटना से दुखी हूं।

उपवास के अंतिम दिन श्री नरेंद्र मोदी ने सद्भावना उपवास पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैं सभी जिलों में जाऊंगा और हर जगह एक दिन सुबह से शाम तक बैठूंगा। मैंने इसके सुफल देखे हैं, एकता, शांति, सद्भाव व भाईचारे की ताकत को महसूस किया है, इसे और ताकतवर बनाना मेरा सपना है। साथ ही अपने बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए स्पष्ट किया कि मैं इतने भर से ही संतुष्ट नहीं हूं। मुझे और शक्ति जुटानी है आगे बढ़ना है। श्री मोदी ने दो टूक कहा, नेतृत्व की कसौटी एक्शन पर निर्भर करती है। आज हमने दुनिया को दिखाया कि यह रास्ता है सबको जोड़कर सबको साथ लेकर चलने का। जब तक वोट बैंक की राजनीति से उठकर विकास की राजनीति नहीं अपनाते तब तक भारत ऊपर नहीं उठ पाएगा। इस कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री ने ही सच्चर कमेटी के साथ कुछ साल पहले हुए संवाद का जिक्र करते हुए कहा, मेरी सरकार अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों के लिए भी कुछ नहीं करती है। मेरी सरकार छह करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है। मैं हर चीज को माइनारिटी–मैजारिटी में नहीं तौलता। मेरे राज्य के नागरिक सभी एक हैं। गुजरात को देश के सामने मॉडल की तरह पेश करते हुए श्री मोदी ने कहा,देश का दुर्भाग्य यही है कि वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित–प्रेरित अर्थ रचना और योजनाएं चलने लगी है। नतीजा यह हुआ कि देश में विकास का माहौल ही नहीं बना। साठ साल बर्बाद हुए। गुजरात उससे बाहर निकल गया। हमने सोचा कि हम चुनाव जीतने के लिए सरकार नहीं चलाएंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री मोदी ने गुजरात के कृषि और औद्योगिक विकास का हवाला दिया। साथ ही सूबे में शांति का रिकार्ड पेश करते हुए कहा, आम आदमी को चाहिए क्या..सिर्फ शांति। क्या यह किसी बहुसंख्यक की शांति की बात हो रही है? शांति सबके लिए होती है और गरीब को सबसे ज्यादा जरूरी होती है।

इस अवसर पर भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू एवं श्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद, श्री शाहनवाज हुसैन एवं श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री प्रकाश जावडेकर, पूर्व क्रिकेटर और सांसद श्री नवजोत सिद्धू, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी, भाजपा गुजरात प्रदेश प्रभारी श्री बलबीर पुंज, मध्यप्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री प्रभात झा, श्रीमती हेमामालिनी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमकुमार धूमल, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सदानंद गौड़ा, अकाली दल नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता मैत्रेयन व थंबी दुरै एवं शिवसेना के प्रतिनिधि भी मंच पर उपस्थित रहे। ■

'प्रधानमंत्री हो रहे हैं कांग्रेस की सड़न से दूषित'

कांग्रेस को देश पर बोझ करार देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन इस पार्टी की सड़न से वह दूषित हो गए हैं। श्री मोदी ने वास्तराल में एक जनसभा में कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब वह अच्छे व्यक्ति थे और हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन, कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से वह दूषित हो गए, और यदि सिंह जैसे लोग कांग्रेस की सड़न से दूषित हो गए तो हमें उस सड़न को हटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश के लिए बोझ बन गयी है। वह सड़ गयी हैं जो जनता के बीच अब दिखती है। भाजपा नेता ने कांग्रेस के अंदर की कलह का भी जिक्र किया और यह बताया कि कैसे केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम एवं केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री बस मूकदर्शक बने हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र द्वारा उनकी अध्यक्षता में बनाई समिति ने महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों की सिफारिश करते हुए आठ महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन प्रधानमंत्री को उसे देखना अबतक बाकी है। इस रिपोर्ट में आवश्यक वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगाने की सिफारिश की गयी थी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान चार समितियां बनाई गयी थीं जिनमें से एक का मैं अध्यक्ष था। मेरी समिति ने महंगाई नियंत्रित करने के लिए आठ महीने पहले रिपोर्ट सौंपी। ■

यूपीए सरकार की नाकामियां हर दिशा में गहराई

भाजपा ही एकमात्र विकल्प बन कर उभरी : अरुण जेटली

गत 17 सितम्बर 2011 को मुम्बई में राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने ''आज की राजनैतिक स्थिति'' विषय पर भाषण दिया, जिसके चर्चित बिन्दुओं को हम यहां संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं:

पिछले कुछ महीनों में सत्तारूढ़ सरकार की विश्वसनीयता में लगातार गिरावट दिखाई पड़ रही है। शासन की दिशा में भटकाव आया है। लगता है जैसे सरकार स्वयं अपने से ही युद्ध करने में लगी हुई है। स्पष्ट ही नेतृत्व का संकट दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री भले ही पद पर विराजमान हों, परन्तु सत्ता से दूर दिखाई पड़ते हैं। अब तो ऐसा भी हो रहा है सत्ताधारी सरकार की जो इच्छा एक परिवार के करिश्मे पर टिकी थी, वह भी कारगर नहीं हो रही है। इस संकट के लिए अनेक कारण हैं।

१ अर्थव्यवस्था की दुर्दशा

राष्ट्र को प्रधानमंत्री पर एक अर्थशास्त्री होने के नाते उनकी काबलियत पर भरोसा था। किन्तु अर्थव्यवस्था की दुर्दशा यूपीए–II सरकार का प्रतीक–चिह्न बन गई है। अब तो राष्ट्र का आर्थिक वातावरण बिगड़ इतना चिंता का विषय बन गया है, जिसे भारत और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में ही माना जा रहा है। देश में निवेश प्रवाह कम होता चला जा रहा है। यहां तक कि भारत के निवेशक भी देश में निवेश करने की बजाए अन्यत्र कहीं निवेश की सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें भी यहां निवेश करना ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा की यह स्थिति निम्नलिखित से समझी जा सकती है:–

- दो वर्षों से भी अधिक समय से मुद्रास्फीति लगभग दो अंकों में पहुंच कर अनियंत्रित अवस्था में पहुंच चुकी है। खाद्य–मुद्रास्फीति एक प्रमुख कारक है जिससे अर्थव्यवस्था में यह मुद्रास्फीति वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सरकार के पास इस मद्रास्फीति को काबू करने के बारे में कोई विचार तक समझ में नहीं आ रहा है। सिवाय इसके कि वह समय–समय पर ब्याज दरों में वृद्धि करती रहती है जिससे अर्थव्यवस्था निष्क्रिय बन जाती है और सरकार पूर्ति की तरफ सुधार करने पर ध्यान ही नहीं दे रही है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण बुरी तरह से आहत हुआ है। राजपथों और टेलीकॉम इन दो क्षेत्रों में जो सफलताओं का गुणगान होता था, वहां हाल के वर्षों में घपले–घोटाले भरे पड़े दिखाई पड़ते हैं।
- एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए विद्युत क्षेत्र के सुधार सचमुच अभूतपूर्व थे। सरकार के आंतरिक निर्णयों ने इसमें धीमी गति लाकर इस क्षेत्र के विस्तार को रोक दिया है।
- सरकार नीति बनाने में पंगु है। कुछेक आर्थिक सुधारों पर तेजी से जो निर्णय लेने चाहिए थे, वहां सरकार ने कोई भी विशेष कदम उठाने की तत्परता नहीं दिखाई है।
- पर्यावरण स्वीकृतियों के कारण बहुत से बड़े–बड़े प्रोजेक्ट अधर में लटके पड़े हैं।
- यूपीए शासन काल में जितने विशाल पैमाने पर भ्रष्टाचार उभर कर सामने आया है, उससे निवेशकों के मन में भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल न मान कर वे निरूत्साहित हो चुके हैं।

उपर्युक्त कारणों से भारत में निवेशकों का उत्साह ठण्डा पड़ता गया है। आर्थिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं। जो अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक भारत की

ओर निवेश करने की बात सोच रहे हैं, उनकी बात तो दूर रही, अब तो देश कापोरेट क्षेत्र भी अपनी सम्पदा का काफी बड़ा हिस्सा देश के बाहर ही स्थानांतरित कर रहा है।

नेतृत्व संकट

लोकतंत्र में कार्पोरेट प्रबंधन के सिद्धांतों पर देश का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है। कंपनियों के सुशासन के लिए तो यह ठीक है जहां बोर्ड निर्णय लेता है और प्रोफेशनल सीईओ कम्पनी का प्रशासन संभालता है। प्रधानमंत्री को सदैव देश और सत्तारूढ़ पार्टी का एक स्वाभाविक नेता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके आदेशों को न तो सरकार और न ही पार्टी मानती है। प्रधानमंत्री के इन गिरते अधिकारों से सरकार का नेता बेबस दिखाई पड़ता है। वह सरकार के रोजमर्रा के कामों में फंसा दिखाई पड़ता है और निर्णायक नीति निर्णय लेने में असमर्थ दिखाई देता है।

होता यह है जब सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा हो तो कांग्रेस का नेतृत्व उच्चतम स्थिति में दिखाई पड़ता है। आज की स्थिति यह है कि प्रधामनंत्री परेशान है, मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं और पार्टी पंगु बनी बैठी है। ऐसा होना किसी भी राजनैतिक पार्टी के लिए अनिवार्य ही है जो प्रमुख रूप से परिवारवाद को उत्तराधिकार के रूप में अपने नए नेतृत्व निर्माण के मार्ग पर चलती है। परिवारवाद मेरिट और मेरिटोक्रेसी दोनों के लिए नकारात्मकता पैदा करते हैं। इससे उन लोगों को हताशा होती है जो सर्वोच्च पद पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं। परिवार का कलंक ऐसी पार्टियों के लिए भारी सीमाएं खड़ी कर देती हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति यह है कि भावी नेतृत्व को छुपा कर रखा जाए, अपनी महत्वपूर्ण नीतियों के विचारों को देश को मालूम ही न होने दिया जाए और फोटो खिंचवा–खिंचवा कर एक लुभावना माहौल पैदा किया जाए। इस प्रकार के नेता तब तो बेहतर होते हैं जब सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा हो। जब चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने हो तो ऐसे नेता ढेर हो जाते हैं। संसद में लोकपाल बिल पर बहस सचमुच खेल बदलने वाली बहस थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बहस से देश को वास्तविक योग्य नेतृत्व का पता चल सकता था या फिर ऐसे लोगों के बारे में लोग जान सकते थे कि कौन केवल फोटो खिंचवा कर अवसरों की तलाश में जुटा है।

इसके विपरीत, भाजपा जैसी पार्टियां (यहां तक कि वामपंथी पार्टियां भी) संरचनात्मक पार्टियां हैं। इनके नेताओं को वर्षों या फिर दशकों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। केवल अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों को ही कुछ मान्यता प्राप्त हो पाती है। आज भाजपा में अनेक योग्य नेता मौजूद हैं। हमारे अधिकांश मुख्यमंत्री युवा है और सर्वोत्कृष्ट कार्य करके दिखा रहे हैं। हमारे केन्द्रीय नेतृत्व के पास जोश भरा है। भाजपा भारत मे नेतृत्व बहस करने की इच्छा रखती है जिससे 'मेरिट' और 'डाइनेस्टी' के बीच की स्थिति स्पष्ट हो सके। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब तक परिवारवाद के करिश्मे का भ्रम फैला रहेगा तब तक भारतीय संसदीय लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप कभी सामने नहीं आ पाएगा।

भ्रष्टाचार

निःसंदेह, हाल के इतिहास में यूपीए सरकार आज तक की सभी सरकारों में भ्रष्टतम सरकार है। घोटालों की संख्या और घोटालों के विशाल परिमाण दोनों ही स्थितियों में यूपीए ने भारत के सार्वजनिक जीवन की विश्वसनीयता को छिन्न–भिन्न करके रख दिया है। प्राकृतिक संसाधन देश की सम्पदा है। यूपीए के अधीन प्राकृतिक संसाधनों का आबंटन भ्रष्टाचार का प्रमुख स्रोत बन गया है। 2जी–स्पेक्ट्रम के आबंटन का घोटाला विशाल स्तर का बहुत बड़ा घोटाला सिद्ध हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना कॉमनवेल्थ खेल ने भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के कारण पूरे खेल को ही बिगाड़ कर रख दिया है। सीएजी की एक–एक रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में, जैसे कोयला, गैस तथा अन्य खनिज पदार्थ, गम्भीर आपत्तियां दिखाई पड़ती हैं। 'नोट के बदले' वोट घाटाले में निश्चित ही सिद्ध हो गया है कि 2008 में विश्वास मत घूसखोरी से कलुषित हो गया था; इसकी बजाए की सरकार भ्रष्टाचार से सीधे टक्कर लेती, उसने इससे इंकार किया और विपरीत दिशाओं में चलने लगी है। लोकपाल बिल बनाने में सरकार का रवैया शत्रुवत है जिससे जांच करने के लिए जिस निष्पक्ष और न्यायोचित तंत्र स्थापना की जानी थी, उसे न करके सरकार अपनी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा रही है।

आतंकवाद

जेहादी तथा माओवादी दोनों ही प्रकार के आतंकवादी विद्रोही फिर से बढ़ते जा रहे हैं। यूपीए सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई ठोस उपाए नहीं कर रही है। जिहादी आतंक के मामले–दर–मामले आते चले जा रहे हैं और सीमा पार के आतंकी या भारतीय मुजाहिदीनों के बारे में किसी भी मामले का समाधान नहीं हो पाया है। यूपीए सरकार की 'नरम और आतंकी' नीति अब तो मुंह चिढ़ा रही है। आज भारत का एक बहुत बड़ा भाग माओवादी हिंसा से ग्रसित है।

परिसंघवाद

यूपीए के कार्यकाल में परिसंघवाद

को भारी धक्का लगा है। सभी गैर–कांग्रेसी राज्य केन्द्र द्वारा उनके साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत कर रहे हैं। राज्यों द्वारा बनाए गए अनेकों कानूनों को राजनैतिक आधार पर राज्यपालों द्वारा सहमति न देने से मामले लम्बित पड़े हैं। राज्यपालों को अनिश्चित काल तक इन्हें अपने पास रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। केन्द्र सरकार इन विधायी तथा एक्जीक्यूटिव क्षेत्रों में दखल दे रही है जहां इन पर राज्यों का हक बनता है। जिस ढंग से एनआईए राज्य की अनुमति के बिना राज्य पुलिस से मामलों को स्थानांतरण कर बिना अपने पास ले रही है, वह इसका उदाहरण है। साम्पद्रायिक हिंसा बिल का कानून बनाने के हाल के प्रयास नितांत भेदभावपूर्ण हैं तो वहीं इनका सम्बन्ध 'सार्वजनिक व्यवस्था' से भी है, जो पूरी तरह से राज्यों के कार्यक्षेत्र में आती है। केन्द्रीय सरकार के ये प्रयास सभी गैर कांग्रेसी राज्यों के लिए चिंता और घबराहट को बढ़ा रहे हैं। उपर्युक्त राजनैतिक स्थिति सत्तारूढ़ सरकार के घमण्ड और आत्मतुष्टि का प्रतीक है। जिस प्रकार से श्री अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलनों से निपटा गया, वह भी इसी प्रयास के प्रतीक हैं।

आज भाजपा गैर–कांग्रेसी राजनैतिक गतिविधियों का प्रमुख ध्यानाकर्षक बनी हुई है। हमारा संगठनात्मक वातावरण सकारात्मक है; हमारी पार्टी के कार्यक्रम बेहद सफल रहे हैं। राजनैतिक मुद्दों पर हमारी स्थिति ने लोगों के साथ समन्वय सम्बन्ध बनाए हैं। संसद में, सरकार औंधे मुंह गिरी पड़ी है। इसके परिणामस्वरूप भाजपा भारत की गैर–कांग्रेसी राजनीति का विकल्प बन कर सामने खड़ी है। हम इस राजनैतिक एजेण्डे का अनुसरण करने के लिए दृढ़तापूर्वक तत्पर हैं। ■

साम्प्रदायिक हिंसा निवारण बिल खतरनाक है : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 10 सितम्बर 2011 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रस्तुत नोट

हमें साम्प्रदायिक सद्भावना के वातावरण को बनाए रखने तथा इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि राज्य की नीति का आधार परिसंघवाद, समानता और निष्पक्षभाव पर टिका होना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा परिचालित प्रारूप बिल एक खतरनाक बिल है। इस बिल के माध्यम से न केवल राज्यों की शक्तियों को छीने जाने की कोशिश है बल्कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात किए जाने के साथ जाति और मजहब के आधार पर भेदभाव करने का प्रयास किया गया है।

आर्थिक विकास से तो सभी को लाभ मिलना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप कमजोर वर्गों को विकास के लाभ प्राप्त हों।

हमारी प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान पर राष्ट्रीय संसाधनों पर गरीबों का प्रथम अधिकार होना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति या मजहब के हों। हमारे सकारात्मक कार्यों का आधार आवश्यकता पर टिका होना चाहिए, न कि ये मजहब आधारित बने।

सिविल उपद्रवों को अत्यंत ध्यान से संभालने की आवश्यकता है। हालांकि राज्य के अधिकारों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए फिर भी हमें सिविल उपद्रवों के साथ निपटते वक्त केवल कानून और व्यवस्था को ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। पुलिस कार्रवाई से पूर्व राजनैतिक संवाद, बातचीत और मेलमिलाप की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।

मजहब और जाति के नाम पर युवाओं के खिलाफ परिवर्तनवादी कार्रवाई की दिशा में नहीं जाना चाहिए। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण आतंकवाद को जन्म देता है। हमारी खुफिया एजेंसियों को अपनी प्रोफेशनल दक्षता को सुधारना होगा और संगठनों के बारे में काफी पहले और पर्याप्त सूचना देनी होगी। हमें इन निकायों की वृद्धि और विस्तार पर लगाम लगानी होगी। शिक्षा, आर्थिक विकास तथा रोजगार इसकी प्रमुख कुंजी है।

हमारे युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी वचनबद्धता अपने राष्ट्र, इसकी विरासत और इसके विकास से जुड़ी होनी चाहिए। ■

कृषि के लिए लोकसभा में अलग से बजट पेश किया जाए : राजनाथ सिंह

lsoknnkrk }kjk

Hkkरतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि के लिए केन्द्र सरकार लोकसभा में अलग से बजट प्रस्तुत करें। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान मोर्चा द्वारा ''गेहूँ की उत्पादन लागत निर्धारण'' के संबंध में दो दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर देशभर से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादक व सबसे बड़ा उपभोक्ता है, देश में कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है अन्यथा आने वाले समय में हमें खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने कहा कि जहां हम विश्व में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन करते थे वहीं आज हम हमारी जरूरत का 50 से 60 प्रतिशत ही उत्पादन कर पा रहे है। आज रेलवे के महत्व को देखते हुए उसका लोकसभा में अलग बजट प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार कृषि है उस पर लोकसभा में कोई चर्चा नहीं होती व सबसे कम समय कृषि को दिया जाता है। हमारी मांग है कि भविष्य में कृषि का लोकसभा में अलग बजट प्रस्तुत किया जाए एवं अभी संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि पर 10 दिन तक चर्चा की जाए, तभी कृषि का महत्व सरकार को ठीक से समझ में आएगा।

श्री सिंह ने कहा कि आज यदि हिन्दुस्तान का किसान सुशोभित होगा उस दिन भारत सुशोभित होगा। यदि देश का किसान खुशहाल होगा तो भारत की खुशहाली स्वतः ही होगी। यदि किसान की जेब में पैसा होगा व किसान धनवान होगा तो देश के उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय स्वतः ही चलेंगे व विकास की गति तेज होगी लेकिन कृषि को उपेक्षित कर देश के विकास की कल्पना केवल कल्पना मात्र है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के 65 वर्षों बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि की समस्या घटने की बजाए बढ़ी है। आज पूरे परिवार को कृषि में झोंकने के बाद भी किसान को भरपेट अनाज नहीं मिल रहा। कभी जीडीपी में कृषि का योगदान 55 प्रतिशत होता था जो आज घटकर 14 से 15 प्रतिशत आ गया है, इसका मतलब यह नहीं कृषि का महत्व कम हो गया है बल्कि सरकार की दोषपूर्ण नीति, कृषि का महत्व कम करने पर आमादा है। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर तीखी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि 2015 तक हम खाद्यान्न उत्पादन दुगुना करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह कृषि की नीति चल रही है। 2015 तो क्या 2030 तक भी हम उत्पादन दुगुना नहीं कर सकते। यह केवल ख्याली पुलाव व सरकारी भाषण है। उन्होंने कहा कि आज यूरोपियन देश अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। श्री सिंह ने अंत में कृषि पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन बिन्दुओं पर काम नहीं करती, हमारा किसान व कृषि दोनों ही खुशहाल नहीं हो सकती। ■

गेहूँ का समर्थन मूल्य १८००/- रु. क्विंटल हो

भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी के बाद मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश धनकड़ ने कहा कि गेहूँ का समर्थन मूल्य 1800/– रु. होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि यह मूल्य शीघ्र लागू किया जाए।

सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र उपहासास्पद : यशवंत सिन्हा

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री यशवंत सिन्हा, सांसद द्वारा 24 सितम्बर को जारी प्रेस वक्तव्य

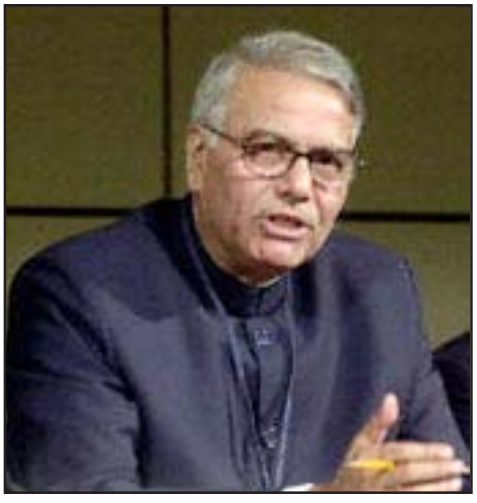

गत 20 सितम्बर 2011 को सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथपत्र से फिर एक बार भारत के लोगों का गहरा मजाक उड़ाया गया है। इस शपथ पत्र में योजना आयोग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 रूपए या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 26 रूपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा और वह बीपीएल लोगों के लिए चलाई जा रही केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इस शपथ पत्र को सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के निर्देशों के अनुसार दाखिल किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को मई 2011 को मूल्यों को देखते हुए बीपीएल मापदण्डों, को अद्यतन करने के लिएक हा गया था। इससे पहले आयोग ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः 20 रूपए और 15 रूपए के आंकड़े प्रदान किए थे और कोर्ट ने कहा था कि इतनी राशि नगरीय क्षेत्रों में 2100 केलौरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 केलोरी की खपत के लिए पर्याप्त नहीं है।

गरीबी का अनुमान समिति–दर–समिति में अलग अलग दिखाई पड़ा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एन.सी. सक्सेना कमेटी ने 29 अगस्त 2009 की अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ''गरीबों की ग्रामीण आबादी का प्रतिशत वर्तमान 29.3 प्रतिशत की कट–आफ लाइन से कहीं अधिक है। अतः कमेटी का कहना था कि बीपीएल दर्जा रखने वाले लागों के प्रतिशत को बहुत अधिक संशोधित कर इसे बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करना आवश्यक है, हालांकि 2400 कैलोरी के मापदण्ड के हिसाब से इसे लगभग बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करना आवश्यक हो जाएगा। अर्जुन सेन गुप्ता का अनुमान था कि हमारी जनसंख्या का 77 प्रतिशत 2004–05 में 20 रूपए की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत पर जीवन व्यतीत कर रहा है। वर्ल्ड बैंक का गरीबी के बारे में अनुमान था कि 2005 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.25 यूएस डालर के आधार पर विश्व निर्धनता को आधार मानते हुए यह 41.6 प्रतिशत बैठती है। योजना आयोग द्वारा बनाई गई तेंदुलकर कमेटी इसी लाइन की नवीनतम कमेटी है।

इसका दुखदतम हिस्सा यह है कि स्वतंत्रता के बाद 64 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हम अभी तक निर्धनता के बारे में कोई संतोषजनक परिभाषा पर नहीं पहुंच पाए हैं। योजना आयोग निर्धनता का अनुमान लगाने वाली नोडल एजेंसी है और भी न जाने कितनी ढेर सारी एजेंसियां है, जो इस काम में जुटी हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास तथा नगर निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, जनसांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्तर्गत एनएसएसओ, गृह मंत्रालय के अन्तर्गत जनगणना महापंजीयक और अब योजना आयोग के 'यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इण्डिया। इससे भ्रम की स्थिति बदतर हालत पर पहुंच गई है।

योजना आयोग के अनुसार कोई व्यक्ति किसी बड़े शहर में चार लोगों के परिवार के साथ 3860 रूपए प्रतिमाह कमा कर आराम से जिन्दगी गुजार सकता है। इस खर्च में न केवल योजना शामिल रहेगा, बल्कि इसमें मकान का किराया, सवारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च भी शामिल है और कपड़े, जूते और अन्य निजी मदे भी शामिल हैं।

जब नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के पहचान करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि गरीबी की परिभाषा की खामियों के अलावा पूर्णतः

आदमी भ्रम ही भ्रम में रहता है। अन्य खाद्यान्न, इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जैसी सब्सिडाइज–युक्त लाभ इन्हीं लोगों के लिए हैं जो बीपीएल की श्रेणी वाले पेंशनधारियों में आते हैं। अतः शहरों और गांवों दोनों में गरीब लोगां की पहचान करना इन गरीबों के लिए जीवन–मरण का प्रश्न खड़ा कर देता है।

इन सारे प्रयासों का बदतर भाग वह है जिसमें प्रत्येक जिले औरी प्रत्येक राज्य में गरीबों की संख्या पर 'कट ऑफ' या उनके सीमित किए जाने की अवस्था को निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार ने यह सीमा पूरी तरह से एकतरफा और यहां तक कि सनकीपन में निर्धारित की है। इससे एक बहुत बड़ी संख्या गरीबी के दायरे से बाहर रह जाएंगे और अपवंचित लोगों के लिए यह बहुत बड़ा कसक पैदा करने वाला साबित होगा। इस प्रकार इंक्लुजिब ग्रोथ गरीबों को बाहर रख कर विकासोन्मुखी बनकर रह जाएगा।

निर्धनता के मुद्दे को केवल सरकार पर ही छोड़ रखना बहुत बड़ी बात हो गई है। न तो प्रधानमंत्री को, न ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष को वास्तविक निर्धनता के बारे में जरा भी मालूम नहीं है। ये शायद ही कभी गांवों में जाते हों और गरीबों से बातचीत करते हों। योजना ओयोग द्वारा प्रधानमंत्री की स्वीकृति से जो शपथपत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उससे ये दोनों दिग्गज अर्थशास्त्री ऐसे उपहासास्पद शपथपत्र से पूरी तरह से मजाक का विषय बन गए हैं। भाजपा पूरी तरह से इन शपथपत्रों को अस्वीकार करती है सरकार से तुरंत ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का आह्वान करती है जिससे विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा कर समाधान निकाला जा सके। ■

भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक

यूपीए की लोकप्रियता और विश्वसनीयता अधमगति तक पहुंची

gkल की घटनाओं से यूपीए सरकार की लोकप्रियता तथा विश्वसनीयता में गिरावट देखने को मिलती है। यूपीए की विश्वसनीयता अधमगति तक पहुंच गई है।

सरकार कीमतों पर नियंत्रण न लगा सकने के कारण आम आदमी पर भारी बोझ पड़ा है।

अब तो आतंक के प्रति सरकार का नर्म रवैया भी उसका मुंह चिढ़ा रहा है।

खुफिया एजेंसियां आतंकवादियों की देश में घुसपैठ रोकने में असमर्थ रहने के कारण तथा साथ ही आतंकवाद सम्बन्धी मामलों को सुलझाने में विफल रहने के कारण एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है।

सरकार भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के मूड को ही समझ नहीं पा रही है। भारत के लोग भ्रष्टाचार से बेहद परेशान हो चुके हैं। जिद्दी रवैया और पुलिस बल के प्रदर्शन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई सही ढंग नहीं है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जिससे किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार होने पर दोषियों को दण्डित किया जा सके और उन पर जुर्माना लगाया जा सके।

साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक को पेश करने के सरकार के प्रयास बेहद भेदभावपूर्ण, अलोकतांत्रिक और भारत के परिसंघीय ढांचे का गहन अतिक्रमण करते हैं, जिनकी अधिकांश राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों ने कटु आलोचना की है। गुजरात में मंत्रिपरिषद की सलाह बिना राज्यपाल द्वारा वहां लोकायुक्त की नियुक्ति की कोई मिसाल नहीं मिलती है और यह असंवैधानिक है।

प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा और उसके साथ हुए करार भारत की क्षेत्रीय अखण्डता के लिए चिंता का विषय बन गए हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के कुछ चर्चित बिन्दु

नोट के बदले वोट घोटाले में आरोपपत्र से निश्चित ही यह सिद्ध हो गया है कि 2008 में विश्वासमत घूसखोरी से प्राप्त किया गया था। यूपीए ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। हम इस मामले में भाजपा सदस्यों की गिरफ्तारी की गहन निंदा करते हैं। घूस देने वाले व्यक्तियों से व्हिसल–ब्लोअर लोगों की तुलना नहीं की जा सकती, जैसा कि सरकार ने किया है। ■

भाजपा-हजकां का हुआ गठबंधन

l oknnkrk }kjk

हरियाणा में कांग्रेस शासन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अक्षमता से हरियाणा राज्य की जनता परेशान हो चुकी है। दोनों दलों ने इन विषयों पर संयुक्त रूप से जनजागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। यह विदित है कि हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की पक्षपातपूर्ण नीतियों पर निर्णय दिये गये हैं। राज्य में किसानों की भूमि को जबरदस्ती छीन कर सरकार द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित की जा रही है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसान सरकारी नीतियों के कारण विस्थापित हो रहे हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब है तथा आधारभूत परियोजनाओं जैसे बिजली, सड़क, स्वच्छ पेय जल की स्थिति भी चिंताजनक है। राज्य में कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने में भी राज्य सरकार विफल रही है। दोनों दलों के गठबंधन ने फैसला किया है कि हरियाणा की जनता को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए जनता के हित में संघर्ष करेंगे।

आगामी हिसार लोकसभा उप–चुनाव को दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। इस उप–चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी एल) के उम्मीदवार को दोनों पार्टियां मिलकर रणनीति बनाकर विजयी बनाने के लिए कार्य करेंगी। राज्य के आगामी विधान सभा चुनावों में विधान सभा की सभी सीटों पर बराबर की संख्या में दोनों दल अपने–अपने उम्मीदवार उतारेंगे। विधान सभा की सीट अनुसार बंटवारे की चर्चा हिसार लोकसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर की जायेगी। आगामी विधान सभा चुनावों के परिणामों के पश्चात गठबंधन के विजयी होने की स्थिति में पहले ढाई वर्ष सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी एल) के नेता श्री कुलदीप बिश्नोई होंगे तथा उप–मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत नेता करेंगे। आगे के ढाई वर्ष में सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत नेता तथा उपमुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी एल) द्वारा मनोनीत नेता करेंगे। गठबंधन द्वारा संचालित सरकार के सभी स्तरों पर दोनों पार्टियों की बराबर की भागीदारी रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य की आठ लोकसभा सीटों पर तथा हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी एल) दो लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। सीटों का चयन दोनों पार्टियों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा।

दोनों दलों ने तय किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर बराबरी के स्तर पर लड़ेंगे तथा हरियाणा में एक स्वच्छ, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कार्य करेंगे जिसमें दोनों पार्टियों की हर स्तर पर बराबर की भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर दोनों पार्टियों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से सांझा अभियान समिति बनायेंगी। दोनों पार्टियां सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगी कि साझे नेतृत्व के अन्तर्गत कार्य करते हुए हरियाणा की जनता का विश्वास प्राप्त करके आगामी चुनाव में गठबंधन विजयी हो सके। इस गठबंधन का पूर्ण विश्वास है कि आगामी समय में हरियाणा में एक नये अध्याय का प्रारंभ होगा, जिसके द्वारा हरियाणा के गौरवशाली इतिहास को पुनः प्रस्थापित करने हेतु समतामूलक विचारों से प्रेरित पारदर्शी, सुशासन वाली सरकार की स्थापना हो सके।■

यूपीए को जनहित की परवाह नहीं : शाहनवाज हुसैन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा 16 सितम्बर, 2011 को दिया गया प्रेस वक्तव्य

देश की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है। यदि यह कहे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ अब आम आदमी के लिए श्राप बन गया है। यही नहीं आम आदमी की खुशहाली का नारा देने वाली यह यूपीए सरकार उसी आम आदमी पर आर्थिक क्रूरता बरपा रही है। गत एक वर्ष में ही 10वीं बार पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि कर इस सरकार ने आम जनता को महंगाई की खाई में डालने का काम किया है। गत 15 मई, 2011 को ही पेट्रोल की कीमत में 5 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी और इस बार 3 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

गौरतलब है कि पहले जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती थी तब यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत में हुई वृद्धि को कारण बताकर तेल कंपनियों की घाटे की बात कहती थी। किंतु इस बार यूपीए सरकार ने एक नया तर्क गढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की तुलना में रूपया कमजोर हुआ है, इस कारण से पेट्रोलियम कंपनियों को घाटे हो रहे हैं। अतः पेट्रोल की कीमत बढ़ाना आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रूपये में 8 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले जुलाई में रुपया जहां 44.42 था वहीं अगस्त में यह 45.32 हो गया। यानी 90 पैसे की गिरावट आई। सितंबर में जहां डॉलर के मुकाबले रुपया 46.68 थी वहीं 15 सितंबर 2011 को 47.56 पर बंद हुई यानी कुल 88 पैसे की गिरावट आई। यदि तेल कंपनियों के आर्थिक विश्लेषक रुपये में इस प्रकार की उथल–पुथल देख रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं कंपनियों को सतर्क किया ? यही नहीं इन तेल कंपनियों ने ऐसी स्थिति में पहले से विदेशी मुद्रा भंडारण का समुचित प्रबंध क्यों नहीं किया ?

यह सरकार का एक अनोखा तर्क है जोकि देश के आर्थिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। यदि कुछ समय के लिए मान भी ले कि सरकार के द्वारा दिया गया तर्क सही है तो डॉलर की तुलना में रूपए के कमजोर होने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? यूपीए सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का ही दुष्परिणाम है कि देश में विदेशी निवेश और घरेलू निवेश लगातार घट रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रूपया डॉलर की तुलना में कमजोर हुआ है। देश की आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुकी है और निवेशक भारत को छोड़कर दूसरे देशों में निवेश करने को मजबूर हो रहे हैं। फिर रूपए एकाएक कमजोर नहीं हुआ है। यदि ऐसी स्थिति थी तो इन बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों और सरकार को क्या इसका पूर्वानुमान नहीं था? और यदि था तो इसके लिए कोई आवश्यक कदम सरकार ने क्यों नहीं उठाए ? जहां तक तेल कंपनियों के घाटे का प्रश्न है तो सरकार का बयान और पेट्रोलियम कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट को देखें तो दोनों में बड़ी विसंगतियां हैं।

सीएजी ने तेल कंपनियों पर किये गए अपने एक अध्ययन में दर्शाया है देश की प्रमुख तेल कंपनियां मुनाफे में रही हैं। यह अध्ययन 31 मार्च, 2010 से 31 मार्च, 2011 के बीच का है।

सीएजी के इस अध्ययन के मुताबिक ओएनजीसी का मुनाफा 31 मार्च, 2010 को 13,403.53 करोड़ रुपये था जबकि 2011 के इसी तिथि को यह मुनाफा बढ़कर 22,455.83 करोड़ रुपये हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यह मुनाफा इसी अवधि में क्रमशः 1476 करोड़ और 1702 करोड़ रुपये था। भारत पेट्रोलियम का मुनाफा इस अवधि में 171,998 लाख और 174,206 लाख रुपये था। इंडियन ऑयल का मुनाफा क्रमशः 10998.68 करोड़ रुपये और 8085.62 करोड़ रुपये था। फिर भी सरकार यह कहती है कि तेल कंपनियां घाटे पर चल रही है। यदि सरकार और तेल कंपनियों का यह तर्क मान भी लिया जाए कि कंपनियां घाटे में हैं तो यह कहां तक उचित है कि इसका भार आम जनता के कंधों पर डाले। वास्तव में मुनाफे कमाने वाली इन कंपनियों की चिंता सरकार को तो है लेकिन आम जनता की बिलकुल इन्हें परवाह नहीं। सरकार महज आम जनता को लूट रही है।

आखिर इस देश में कोई सरकार है या नहीं। यदि सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करेगा तो एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार क्या करेगी ? यह सरकार अच्छी तरह से जानती है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का मतलब है देश में महंगाई और भी बढ़ जाना। पहले यह यूपीए सरकार कहती थी कि महंगाई बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ती है। आज हालात यह है कि महंगाई बेलगाम बढ़ रही है और जीडीपी घट रही है।

इसी सप्ताह जारी आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई एक बार फिर डबल डिजीट के करीब पहुंच गई है। फिर यह वृद्धि और कितनी महंगाई बढ़ाएगी? आखिर यह सरकार कब तक गरीब के पेट पर लात मारती रहेगी और दुधमुंहे बच्चे का निवाला छीनेगी? और आम जनता कब तक महंगाई की मार झेलता रहेगा ? हम जानते हैं कि कांग्रेसनीत यूपीए सरकार एक अहंकारी और तानाशाही रवैया अपनाए हुए सत्ता के मद् में चूर है। लेकिन, आज हम इनके सहयोगी दलों से यह पूछना चाहते हैं कि आप कब तक इस अहंकारी और अमानवीय सरकार का साथ निभाते रहेंगे ? आज यूपीए गठबंधन के सहयोगी दलों को भी यह आत्म–मंथन करना पड़ेगा कि वे कब तक इस देश की जनता को महंगाई की खाई में धकेलते रहेंगे और वे कांग्रेस के सहभागी बने रहेंगे।

हम सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि आम जनता की बुनियादी आवश्यकता रसोई गैस की कीमत में कुछ माह पूर्व ही भारी वृद्धि की गई। और एक बार फिर से केन्द्र की यूपीए सरकार रसोई गैस में वृद्धि करने की बात कर रही है। हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि वह इस आवश्यक ईंधन में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करे। भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करती है कि वह पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को तुरंत वापस ले और बेलगाम बढ़ती महंगाई पर तत्काल रोक लगाए। ताकि आम जनता को राहत मिल सके।■

नरेन्द्र मोदी के सद्भाव अनशन के समर्थन में दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सांकेतिक उपवास किया

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए तीन दिवसीय सद्भावना उपवास के समर्थन में 17 सितम्बर को भाजपा दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा ने जंतर मंतर पर सांकेतिक उपवास रखा। उपवास में हजारों की संख्या में दिल्ली से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

इस अवसर पर भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने उपवास पर बैठे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज देश में गुजरात ही एक ऐसा उदीयमान प्रदेश है जहां की विकास गति 11 प्रतिशत से ऊपर है। मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में सन् 2008 के बाद कोई भी दंगा–फसाद गुजरात में नहीं हुआ। इसी कारण गुजरात प्रदेश आज विश्व में भारत का सिर ऊंचा कर रहा है।

अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आतिफ रशीद ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा कर पाने में सक्षम है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्वकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए जितने कार्य किए गए, उतने कार्य किसी भी अन्य सरकार ने नहीं किए। कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों का सिर भावनात्मक शोषण करती है।■

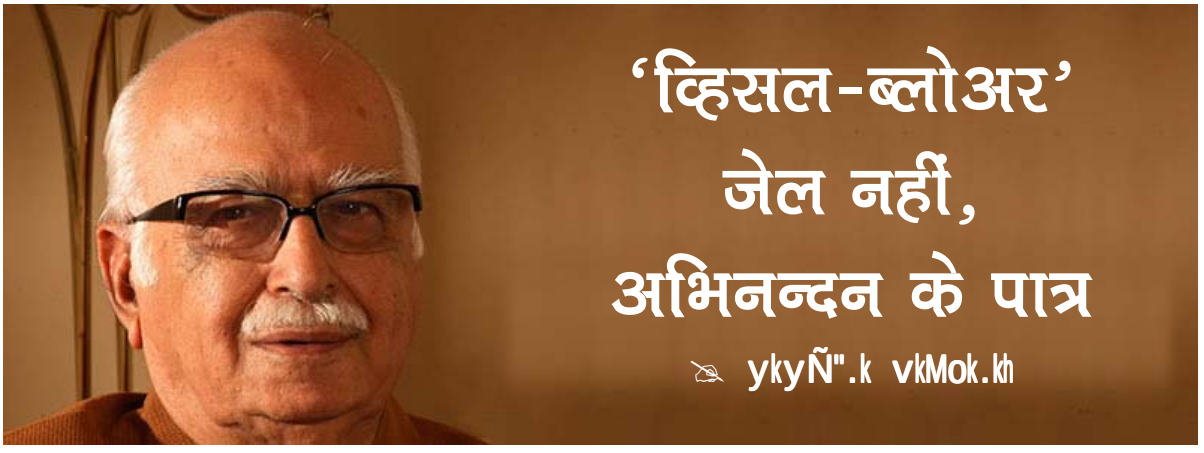

'व्हिसल-ब्लोअर' जेल नहीं, अभिनन्दन के पात्र

ykyÑ".k vkMok.kh

Vगस्त, 2005 में राष्ट्रपति ने 'लोक प्रशासनिक प्रणाली को पुनर्गठित करने हेतु एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करने' के उद्देश्य से श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया था।

आयोग की चौथी रिपोर्ट का शीर्षक है 'शासन में नैतिकता'। इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में सबसे ऊपर महात्मा गांधी का निम्न उद्धरण दिया गया है:

एक इन्सान के रूप में हमारी महानता इसमें इतनी नहीं है कि हम दुनिया को बदलें – वह तो परमाणु युग का रहस्य है – जितनी इसमें है कि हम अपने को बदल डालें।

प्रस्तावना की शुरूआत इस पैराग्राफ से होती है:

महात्मा जी की एक सुदृढ़ और खुशहाल भारत की दृष्टि –पूर्ण स्वराज्य– कभी वास्तविकता में नहीं बदल सकती यदि हम आमतौर पर राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से भ्रष्टाचार के खात्मे के मुद्दे का समाधान नहीं कर लेते।

रिपोर्ट आगे वर्णन करती है कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में 'व्हिसल–ब्लोअरों' ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसलिए 'व्हिसल–ब्लोअरों' को सुरक्षा देने वाले कानूनों को भ्रष्टाचार के विरूद्ध कानून में शामिल करना चाहिए। रिपोर्ट कहती है:

सूचना देने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार के बारे में सूचना प्रदान करने में एक आवश्यक भूमिका अदा करते हैं। किसी

"भ्रष्टाचार, घोटाले की सूचना देने वाला व्यक्ति" (व्हिसल–ब्लोअर) ये शब्द हमारे शब्द कोश में अपेक्षाकृत हाल ही में जुड़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, डेनियल एल्सबर्ग नाम का व्यक्ति जो तथाकथित "पैंटागोन पेपरों" पर "सीटी बजाता था" के दुःख और विपत्ति के बाद, वाटरगेट के बाद के युग में, सीटी बजाना केवल संविधि द्वारा न केवल सुरक्षित कर दिया गया है, बल्कि नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों के रूप में प्रोत्साहित भी किया जाता है।

विभाग/एजेंसी में काम करने वाले लोक सेवक अपने संगठन में अन्य लोगों के पूर्ववृत्तों और गतिविधियों से परिचित होते हैं। तथापि, प्रायः वे बदले की भावना के डर से इस सूचना को देने के इच्छुक नहीं होते।

यदि पर्याप्त रूप से सांविधिक संरक्षण प्रदान कर दिया जाए तो इस बात की बहुत ही संभावना होती है कि सरकार को भ्रष्टाचार के बारे में पर्याप्त सूचना मिल सकती है।

"भ्रष्टाचार, घोटाले की सूचना देने वाला व्यक्ति" (व्हिसल–ब्लोअर) ये शब्द हमारे शब्द कोश में अपेक्षाकृत हाल ही में जुड़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, डेनियल एल्सबर्ग नाम का व्यक्ति जो तथाकथित "पैंटागोन पेपरों" पर "सीटी बजाता था" के दुःख और विपत्ति के बाद, वाटरगेट के बाद के युग में, सीटी बजाना केवल संविधि द्वारा न केवल सुरक्षित कर दिया गया है, बल्कि नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों के रूप में प्रोत्साहित भी किया जाता है।

ऐसे संरक्षण की व्यवस्था वाले कानून ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में हैं।

विधि आयोग ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट डिस्कलोजर (प्रोटेक्शन ऑफ इन्फार्मर्स विधेयक

(Public Interest Disclosure / Protection of Informers/Bill) का प्रस्ताव सुझाया है जिसमें 'व्हिसल–ब्लोअर' को सुरक्षा देने का प्रावधान है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट उन दो भारतीयों के दुःखद उदाहरण का वर्णन करती है जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने का अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए अपनी जान की कीमत चुकाई।

रिपोर्ट कहती हैः इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई ओ सी) में काम करने वाला मंजुनाथ शणमुखम भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ का स्नातक था। उसने पेट्राल पंपों के स्वामियों द्वारा मिलावट के विरूद्ध अपनी लड़ाई में रिश्वत लेने से इंकार कर दिया और अपने जीवन को दी गई धमकियों की भी परवाह नहीं की। उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसे 19 नवम्बर, 2005 को तथाकथित रूप से भ्रष्ट पेट्रोल पंपों के मालिकों के आदेश पर गोली से मार दिया गया।

''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में कार्यरत सत्येन्द्र दूबे ने सड़कों के निर्माण में फैले अत्यधिक भ्रष्टाचार का खुलासा किया। वह भी 27 नवम्बर, 2003 को मृत पाया गया।''

''''

मैंने इन सब का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में 'नोट के बदले वोट' काण्ड सर्वाधिक शर्मनाक है।

यह केवल यूपीए सरकार के ऊपर काला धब्बा नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र पर भी कीचड़ समान है।

इन तीन सांसदों ने सरकार के काले कारनामे को उजागर कर लोकतंत्र की उत्कृष्ट सेवा की है। और सरकार जिसकी एआरसी रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि इस तरह भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले इस तरह के काम को न केवल वैधानिक सुरक्षा देने की जरूरत है अपितु यह एक नैतिक आवश्यकता भी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वैधानिक संरक्षण भले ही आवश्यक होंगे, लेकिन संसद सदस्यों के लिए नैतिक आचरण ही स्वयं में न्यायोचित है।

6 सितम्बर की शाम को जब मैंने सुना कि 'व्हिसल–ब्लोअर' के रूप में काम करने वाले तीन में से दो सांसदों को जेल भेज दिया गया है तो मैं अत्यन्त विचलित हो गया। इसने मुझे सत्र के अंतिम दिन सदन में यह कहने को प्रवृत्त किया कि "मुझे मालूम था कि वे रिश्वत की समूची राशि को सदन के पटल पर रखने का इरादा रखते हैं। यदि मुझे लगता कि वे कुछ गलत कर रहे हैं तो दल का नेता होने के नाते मैं उन्हें रोकता। हालांकि यदि सरकार सोचती है कि उन्होंने जो किया वह गलत था और इसलिए उन्हें जेल में भेज दिया गया, तो मैं सत्ता पक्ष को बताना चाहूंगा कि मैं उनसे ज्यादा दोषी हूं क्योंकि मैंने उन्हें रोका नहीं। मुझे भी तिहाड़ भेज दो।"

सन् 2008 में जिन तीन सांसदों ने इस काण्ड को उजागर कर इतिहास बनाया उनमें से कुलस्ते जनजातीय सामान्य से हैं, भगोरा और अर्गल दोनों अनुसूचित जाति से हैं।

साफ है कि जिन लोगों ने पैसा लेकर इनसे सम्पर्क किया वे मानते थे कि इन सांसदों को फांसा जा सकता है। अर्गल वर्तमान में सांसद हैं अतः उनका केस स्पीकर द्वारा एटार्नी–जनरल को भेजा गया है। ■

हिमाचल प्रदेश

गरीब परिवारों की आर्थिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट को वापस ले केंद्र सरकार : भाजपा

शिमला, 23 सितबंर (हि.स.)।प्रदेश भाजपा ने योजना आयोग द्वारा वीपीएल परिवारों के खर्च, खान पान पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट को आम गरीब परिवारों के साथ धोखा बताया है तथा केंद्र सरकार तथा योजना आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये हल्फनामें को वापिस लेने की मांग की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से जारी बयान मे प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा कि वातानुकूलित कार्यालयों में बैठ कर योजना बनाने वाले उन अधिकारियों को शायद बाजार मूल्यों का पता नहीं है अथवा उन्हें बाजार से कोई वस्तु लेनी नहीं पड़ती यदि बाजार भाव व गरीब के जीवन चलाने की स्थिति का पता होता तो शायद योजना आयोग शहरी गरीब की आय 965 तक तथा ग्रामीण गरीब की सीमा आय को 781 रू. माह नहीं आंकता तथा बाजार भाव के आधार पर वीपीएल (गरीब) परिवारों के जीवन यापन पर व्यवहारिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती लेकिन योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में यह रिपोर्ट देकर कि शहर में 965 रू. मासिक व ग्रामीण क्षेत्रों में 781 रू. से अधिक कमाने वाले को गरीबी की रेखा में रखा जाय यह रिपोर्ट हास्यास्पद तथा आम गरीब पर महंगाई की मार के जख्मों पर नमक छिडकने जैसा है। गणेश दत्त ने कहा कि इस तरह 26 रू. रोज पाने वाला व्यक्ति बी.पी.एल. परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। महंगाई के इस युग में 100 रू. प्रति रोज में भी गुजारा करना संभव नहीं है लेकिन योजना आयोग इस प्रकार की रिपोर्ट देकर जहां गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है वहीं समाज की समस्या से भी योजना आयोग अनभिज्ञ लगता है।■

अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बना मध्य प्रदेश

& eukst dqekj JhokLro

tनहित में किये जाने वाले कार्यों को न केवल व्यापक सराहना मिलती है, बल्कि उनका यथोचित स्तर पर अनुसरण भी किया जाता है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष लागू किया गया लोकसेवा प्रदाय गारंटी कानून ऐसी ही एक पहल है, जिससे प्रेरित होकर अनेक राज्यों ने ऐसा ही या कुछ संशोधनों के साथ कानून लागू कर दिया है। कुछ अन्य राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में है। लोक सेवा गारंटी के मामले में मध्य प्रदेश की राह पर चलने के इच्छुक राज्यों की फेहरिस्त कम नहीं है। म.प्र. की पहल और क्रियान्वयन से मिले परिणामों की वजह से अन्य राज्यों पर भी इसे अपने यहां लागू करने का दबाव बढ़ा।

मध्य प्रदेश की तर्ज पर कुछ संशोधनों के साथ अलग–अलग नामों से कई राज्यों ने इसे में अपनाया है। हालांकि कुछ लोग बाबूशाही और असहयोग के कारण लोगों में पैदा हुई निराशा की भावना की वजह से शिखर पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन को भी इसका श्रेय देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्ना हजारे के आंदोलन के पहले से लागू है। सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने का लगभग इसी तरह का कानून लागू करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। इसी साल छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। बिहार ने सार्वजनिक सेवा में खामियों से जनता को छुटकारा दिलाने के प्रतीकात्मक कदम के रूप में इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। यहां जुर्माने की अधिकतम राशि पांच हजार रूपये है।

हिमाचल प्रदेश ने मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश जन सेवा गारंटी विधेयक–2011 पास किया है। इसका उद्देश्य अच्छा शासन, प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही तथा जनता को समयबद्ध तरीके से सेवायें मुहैया कराना है। इस अधिनियम में भी अधिकतम पांच हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली में भी 15 सितंबर 2011 से समयबद्ध सेवा आपूर्ति नागरिक अधिकार अधिनियम–2011 लागू हो गया है। इसी तरह राजस्थान मंत्रिमण्डल ने भी राजस्थान सार्वजनिक सेवा आपूर्ति गारंटी विधेयक 2011 को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा है।

छत्तीसगढ़ राज्य भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम को अंतिम रूप देने में लगा है। उत्तर प्रदेश भी ऐसा ही जनहित गारंटी कानून बनाने की ओर अग्रसर है। पंजाब में भी सेवा का अधिकार कानून बनाने के बारे में गंभीरता से विचार चल रहा है। प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार से रहित समाज के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बाद प्रदेश में एक और बड़ी पहल होने जा रही है, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक–2011 के रूप में। यह फिलहाल राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में लंबित है। इस अधिनियम में भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में किया जाकर उसके बाद 6 माह में भ्रष्ट आचरण से अर्जित संपत्ति को राजसात करने का प्रावधान है। ऐसी राजसात की

गई संपत्ति का उपयोग लोकहित में किया जायेगा।

आम जनता को समय–सीमा में लोक सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किये गये मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम को एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस कानून की वजह से आमजन का हौसला बढ़ा है, अपना काम कराने के लिए अधिकारियों के समक्ष गिड़गिड़ाने और याचनाभाव की मानसिकता अधिकार और ताकत में तब्दील हुई है। प्रदेश में यह अधिनियम सही मायने में नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने का अभिनव प्रयास साबित हो रहा है। तभी तो देश के कई राज्य आज मध्य प्रदेश के सुशासन के इस मॉडल को अपनाने जा रहे हैं। पूरे देश में इस अधिनियम की लोकप्रियता की मची धूम से स्वयं प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने बीना रिफायनरी के लोकार्पण समारोह के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस अधिनियम के बारे में जानकारी ली।

दरअसल इस अधिनियम के केन्द्र में एकात्म मानववाद के प्रणेता और प्रखर सामाजिक चिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय की वह सोच निहित है, जिसमें उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने का सपना देखा था। पंडित जी का मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के प्रति शासन के कर्तव्यों की पूर्ति का उपकरण है, जिसकी प्रभावशीलता, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन में निहित है। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंत्र को जन के प्रति और अधिक जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के लिए लोक सेवा प्रदाय अधिनियम में कई कड़े प्रावधानों को समाहित कराया है।

वास्तव में इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि आजादी के 64 वर्षों बाद भी सरकारी तंत्र के जेहन में स्वयं को जनता से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति और अंग्रेजी शासनकाल की औपनिवेशिक मानसिकता का पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पायी है। इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता था। फलतः सुशासन के माध्यम से व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री ने प्रशासन में कई नवाचारों को अपनाया, जिनमें जनसुनवाई, समाधान ऑन लाइन, जनदर्शन, परख, आइडियॉज फॉर सी.एम., ई–टेण्डरिंग जैसी कोशिशों के सार्थक परिणाम भी मिले हैं।

प्रदेश का लोक सेवा गारंटी अधिनियम पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून है, जिसमें तयशुदा समय–सीमा में सेवा नहीं देने वाले शासकीय सेवक को जुर्माना भरना पड़ता है। ढ़ाई सौ रुपये दिन से शुरू होकर जुर्माने की रकम पांच हजार तक हो सकती है। जुर्माने की राशि प्रभावित आवेदक को हर्जाने के रूप में देने का प्रावधान है। जुर्माना के अलावा अपना रवैया न बदलने वाले कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी इसमें प्रावधान है।

प्रदेश में इस अधिनियम का अब असर भी दिखने लगा है। हाल ही में सतना जिले के कलेक्टर सुखबीर सिंह ने प्रसूति सहायता के छह विभिन्न मामलों में आवेदकों को समय–सीमा में हितलाभ नहीं मुहैया कराने की वजह से नगर पंचायत रामपुर बघेलान के तीन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों क्रमशः के.एस. मिश्रा, सिद्धार्थ खरे और संजय सोनी तथा लिपिक राधेश्याम तिवारी पर कुल 12 हजार रूपये का जुर्माना किया है। यह जुर्माना संबंधितों के वेतन से वसूला जायेगा। प्रदेश में अगस्त 2010 से लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम को महज एक वर्ष की अल्प अवधि में ही खासी लोकप्रियता हासिल हो गई है। तभी तो प्रदेश भर में करीब 60 लाख लोगों का काम तय समय–सीमा के भीतर हुआ। ऑन लाईन व्यवस्था के तहत बीते डेढ़ महीने में 85 हजार से ज्यादा आवेदनों पर संबंधित लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। यह भले ही कोई जादुई आंकड़ा जैसा न दिखे लेकिन साल भर में हासिल की गई इस उपलब्धि को कम भी नहीं कहा जा सकता।

राज्य शासन ने इस कानून पर प्रभावी अमल और कुशल संचालन के लिए एक अलग लोक सेवा प्रबंधन विभाग बनाया है। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर 2011 से विकासखण्ड मुख्यालय में भी ऑन लाइन आवेदन लेने की व्यवस्था शुरू हो जायेगी। अधिनियम को व्यापक स्वरूप देते हुए 13 विभागों की 25 नई सेवाओं को इसमें और शामिल किया जा रहा है। वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में 9 विभागों की 26 सेवायें अधिसूचित हैं। सुदूर अंचलों में उप लोक सेवा केन्द्र और मोबाइल सेवा केन्द्र कायम करने की भी योजना है।

कानून के सभी प्रावधानों का जनक और अन्य राज्यों के लिए मॉडल अधिनियम की राह दिखाने वाला मध्य प्रदेश का लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम ही है। ये प्रावधान उन हर सेवाओं के लिए है, जिनके लिए आम जनता को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे और लेन–देन करना पड़ता था। इनमें हैण्डपंपों की मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता, ऋण पुस्तिका प्राप्त करना, नल कनेक्शन, निवासी प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड बनाना आदि के काम शामिल है।■ ***(हिन्दुस्थान समाचार)***

भुवन चंद्र खंडूरी बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री

Oरिष्ठ भाजपा नेता श्री भुवनचंद्र खंडूरी ने विक्रम संवत के अनुसार अनंत चौदस के दिन राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाल ली।

गत 11 सितम्बर 2011 को राज्यपाल मारग्रेट अल्वा ने श्री खंडूरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री खंडूरी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ईश्वर के नाम पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्री खंडूरी ने कहा कि राज्य की जनता के हित के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया है और आगे भी कार्य करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वह पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्य के कल्याण के लिए वह भाजपा की नीतियों को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे।

भाजपा ने हमेशा उत्तराखंड की महान जनता के हितों के लिये कार्य किया है और आगे भी इस कार्य को जारी रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के अथक प्रयासों के चलते ही इस राज्य का गठन किया गया था। वह आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे।

इसके पूर्व खंडूरी के नयी दिल्ली से देहरादून पहुंचने पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्थानीय हेलीपैड पर जबर्दस्त स्वागत किया तथा उनको मालाओं से लाद दिया। कार्यकर्ता जोर शोर से नारे भी लगा रहे थे। निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिन में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों बंशीधर भगत, मदन कौशिक, खजान दास, गोविन्द सिंह बिष्ट तथा कुछ अन्य लोगों के साथ राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। श्रीमती अल्वा ने श्री निशंक का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं तथा उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। निशंक के इस्तीफा दिये जाने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार खंडूरी को आज नया नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद श्री खंडूरी ने श्रीमती अल्वा से मिलकर अपना समर्थन पत्र भी सौंपा। अल्वा ने उनके अनुरोध पत्र को स्वीकार कर लिया। ■

एक माह में राज्य के सभी मंत्री और अधिकारी करें अपने संपत्तियों की घोषणा-सीएम

उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने प्रदेश में अन्ना के एजेंडे को लागू करने की घोषणा की है। गत 11 सितम्बर को देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद सचिवालय में हुई खंडूरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने राज्य के सभी मंत्रियों और आएएस और आईपीएस अधिकारियों को एक माह के अंदर अपनी संपत्तियों की घोषणा करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ तेवर दिखाए है उससे भ्रष्टाचार से त्रस्त प्रदेश की जनता में एक नई आस जगी है। श्री खंडूरी ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही अन्ना के लोकपाल पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसके दायरे में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाएगा जिससे प्रदेश में एक सशक्त लोकपाल की सोच को पूरा किया जा सके।इसके साथ ही यहां पर सिटीजन चार्टर का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और उसे जनहित में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने सूचना के अधिकार को राज्य में और मजबूत करने की बात कहते हुए 56 घोटालों की जांच में भी तेजी लाने के संकेत दिए हैं। ■

निर्दोष आदिवासी नेताओं की रिहाई को लेकर भाजपा ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 22 सितम्बर 2011 को नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर तिहाड़ जेल में बंद मध्यप्रदेश के आदिवासी नेता फग्गनसिंह कुलस्ते एवं महावीरसिंह भगोरा की रिहाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल मे वरिष्ठ नेता दिलीपसिंह भूरिया, सांसद माकनसिंह सोलंकी, ज्योति धुर्वे, वरिष्ठ मंत्री विजय शाह, जगन्नाथ सिंह, रंजना बघेल, विधायक कुंवर सिंह, जयसिंह मरावी, देवीसिंह सैय्याम, रेलम चौहान, अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धुर्वे, यशवंतसिंह दरबार, दलपतसिंह परस्ते, सुदामा सिंह, मुकामसिंह किराड़े शामिल थे। हम यहां ज्ञापन का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:–

दिनांक 22.09.2011

प्रति,
ek- egkefge jk"Vifr egkn;k
भारत, नई दिल्ली

जैसा कि आपको विदित है 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में विश्वासमत के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तीन सांसदों श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री अशोक अर्गल व श्री महावीर सिंह भगौरा ने संसद के पटल पर करोड़ों रूपये के उन नोटों को सबूत के रूप में रखा जो कि उन्हें तत्कालीन कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार को बचाने के लिए उनके प्रतिनिधियों द्वारा रिश्वत के तौर पर तथाकथित रूप से दिये गये थे, जिसके फलस्वरूप उनसे यह अपेक्षा थी कि वे विश्वासमत पर मतदान के दौरान या तो अनुपस्थित रहेंगे अथवा विश्वास मत के पक्ष में मतदान करें।

भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसदों ने संसदीय गरिमा एवं देश के लोकतंत्र को बचाने हेतु वीरतापूर्वक अपनी चिंता न करते हुए इस पूरे विषय को संसद के परम संरक्षक एवं संस्था प्रमुख तत्कालीन अध्यक्ष, लोकसभा के सामने उद्घाटित किया, यह भी उल्लेखनीय है कि इस पूरे षड्यंत्र में उपयोग की गई राशि को भी हमारे सांसदों ने घटनाक्रम के उल्लेख के साथ–साथ संसद के पटल पर जमा कर दिया, यहां यह भी स्मरणीय है है कि इस पूरी घटना की रिकार्डिंग शुरू से लेकर अंत तक कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार की मंशा का पर्दाफाश करने हेतु एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार चैनल द्वारा की गई, जो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में मौजूद है।

देश में मौजूद भ्रष्टाचार निरोधक कानून की मूल भावना के तहत रिश्वत काण्ड की सूचना देने वाले व्यक्ति होने

के नाते भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आवेदक मानते हुए जांच संस्थाओं को प्रकरण दर्ज कर जांच करनी चाहिए थी। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इसे पूरे प्रकरण में आवेदक सांसदों को ही दुर्भावनापूर्वक आरोपी बना दिया गया तथा इस प्रकरण के लाभार्थी तथा संयोजकों को संदिग्धों की सूची में अन्वेषण के दौरान रखना भी उचित नहीं समझा गया।

अतः यह पूरी जांच प्रक्रिया अन्याय एवं दुर्भाग्य का विषय है तथा इस प्रकार की जांच संस्थाएं व प्रक्रिया हमारे देश के पिछड़े, आदिवासी, गरीब, सांसदों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार तथा इन वर्गों के अपमान का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर यह संदिग्ध जांच प्रक्रिया संसद की उस मूल भावना के भी प्रतिकूल है जिसमें देश की संसद ने एक मत होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति व्यक्त की है, इस कार्यपद्धति के फलस्वरूप देश में ईमानदारी, सत्य एवं निष्ठा के प्रतीक सीखचों के पीछे हैं तथा भ्रष्टाचार के पोषक कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार में हैं।

माननीय महामहिम महोदया, यहां पर यह बताना भी उल्लेखनीय होगा कि श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि चार बार के लोकसभा सांसद हैं, एक बार के विधायक हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे हैं। यह सांसद उस मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जन नेता हैं, जो कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए न केवल कृत संकल्पित हैं अपितु हमारे इस दिशा के प्रयास, जैसे– भ्रष्टाचार निवारण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना, लोकसेवा प्रदाय गारंटी कानून एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधनों, के साथ देश में एक प्रमुख तथा अग्रणी राजनैतिक दल व सरकार के रूप में स्थापित हैं।

अतः आपसे संविधान के संरक्षक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जनप्रतिनिधियों के रक्षक होने के नाते यह विनम्र निवेदन है कि इन वर्गों के सम्मान की रक्षा करें तथा अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने महत्वपूर्ण अभिमत को इनके पक्ष में देकर प्रदेश तथा देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ हो रहे इस सरकार प्रायोजित अत्याचार के दौरान इन्हें न्यायोचित संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।

Hkonh;
¼çHkkr >k½

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राजस्थान

सुशासन के नाम पर सरकार केवल विज्ञापनबाजी कर रही है : भाजपा

जयपुर 12 सितम्बर,(हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता ज्योति किरण ने कहा कि सरकार का श्रम शक्ति नियोजन विरोधाभासी तथा असफल है। सरकार प्रशासन को शहरों तथा गांवो तक ले जाने के दिखावटी प्रयत्न कर रही है। सुशासन के दावे पर जमकर विज्ञापनबाजी की जा रही है। जनता से सीधे–सीधे जुडे विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस इन्हीं में डेढ़ लाख पद खाली पड़े है और यही नहीं इन खाली पदों में प्रतिवर्ष बढोतरी हो रही है।

उन्होंने कहा कि उर्जा तथा अन्य इनपुट्स के लगातार बढते दामो के कारण औद्योगिक विकास चौपट है, जिसके कारण औद्योगिक रोजगार वृद्धि की दर लगातार गिरी है। सरकारी रोजगार श्रम शक्ति के कुप्रबन्धन के कारण बढ़ नही रहे। इसका सामूहिक प्रभाव यह है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में रोजगार वृद्धि की दर बेहद कम है।

ज्योति किरण ने कहा कि बढते व्यवसायिक शिक्षण संस्थान तथा घटते रोजगार के अवसरों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में एक ढांचागत असंतुलन खडा कर दिया है, इससे सामाजिक अपराध तथा आर्थिक विषमताएं और भी बढेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करती है कि इस ओर तुरन्त ध्यान दे तथा राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये, नहीं तो राज्य के युवा आन्दोलन की राह पकडने पर मजबूर हो जायेंगे। ■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर

रक्तदान शिविर का आयोजन

& laoknnkrk }kjk

Hkk रतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरूष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितम्बर को भाजपा के 1500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित महारक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस शिविर में दिल्ली के पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर अस्पताल, रोटरी क्लब, रेडक्रॉस सोसाईटी, जी.टी.बी. अस्पताल, लॉयन्स क्बल, हिन्दूराव अस्पताल ने रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर सुबह से शाम तक रक्त देने वाले उत्साही कार्यकर्ताओं का रक्तदान के लिए तांता लगा रहा। रक्तदान में प्राप्त रक्त दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा ताकि कोई भी मरीज रक्त के बगैर प्राण न त्यागे।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय सनातन कल्याणकारी परंपरा में सदैव नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। भारतीय संस्कृति ही – सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की विचारधारा पर आधारित रही है। इसलिए प्राचीन काल से ही भारतीय सनातन परम्परा समाज के वंचित तबके को ऊंचा उठाने की ही रही है। भारत में मैं नहीं हम को प्राथमिकता दी गयी और इसी अवधारणा के अनुसार संतपुरूष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का महामंत्र देश को दिया। उनका मानना था कि जब तक पंक्ति के आखिर में खड़े व्यक्ति तक सभी सुख–सुविधाएं नहीं पहुंच जाती हैं, समाज उत्थान का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। भाजपा इसी स्वप्न को साकार करने में लगी है। भाजपा के लिए सत्ता एक साधन है, लक्ष्य नहीं। ऐसा ही लक्ष्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश को दिया था।

रक्तदान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा, श्री विजय गोयल, सैयद शाहनवाज हुसैन, श्री रामेश्वर चौरसिया, सुश्री वाणी त्रिपाठी, श्री प्रभात झा, श्री विजय शर्मा, श्री रमेश बिधूड़ी, प्रो. रजनी अब्बी, विधायक डॉ. हर्ष वर्धन, प्रो. जगदीश मुखी, श्री श्याम लाल गर्ग, श्री करण सिंह तंवर, श्री सतप्रकाश राणा, चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक तथा रक्तदान शिविर के आयोजक डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता, सहित अनेक पार्टी पदाधिकारियों तथा वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि अपनी सामाजिक सेवा के संकल्प के तहत ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आज प्रदेश भाजपा ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महारक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ■

संप्रग सरकार ने देश का मस्तक दुनिया की नजर में नीचा किया : भाजपा

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बंगलादेश दौरे के दौरान असम की लगभग 700 एकड़ भारत की भूमि बंगलादेश को अंतरित किए जाने के प्रबल विरोधस्वरूप 10 सितम्बर को भाजपा ने जमीन वापस लेने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया। इसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की।

धरने में राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री विजोय चक्रवर्ती (असम), राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री राम लाल, राष्ट्रीय महामंत्रीगण श्री अनंत कुमार, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री जगत प्रकाश नड्ढा, श्री विजय गोयल, प्रदेश भाजपा के सह–प्रभारी श्री रामेश्वर चौरसिया, असम राज्य के भाजपा सांसद और विधायक, श्री चंदन मित्रा, आर.पी. सिंह, विशाखा शैलानी, रमेश बिधूड़ी, आशीष सूद, अनिल गोयल सहित अनेक केन्द्रीय और प्रदेश के नेताओं ने हिस्सा लिया। इनमें से अनेक नेताओं ने धरने पर बैठे लोगों को सम्बोधित किया।

महामंत्री संगठन श्री राम लाल ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान संप्रग सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हजारों बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली। भारत की मदद और कृपा से ही बंगलादेश नामक देश का उदय विश्व मानचित्र पर हुआ। आज उसी बंगलादेश को भारत के कमज़ोर और लचर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम राज्य की बेशकीमती जमीन मुत में उपहार के रूप में भेंट कर दी जो बंगलादेश अपने यहां भारत विरोधी आतंकवादियों को खुलेआम संरक्षण दे रहा है। भारत–बंगलादेश की लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा पार करके अवैध बंगलादेशी घुसपैठिए भारत में आकर बस गए हैं। यही लोग भारत के विरोध में अनेक गतिविधियां चला रहे हैं। होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री सख्ती अपनाते हुए बंगलादेश सरकार से कहते कि वह अवैध बंगलादेशियों को अपने यहां वापस बुलाए और अपनी भूमि से भारत विरोधी गतिविधियां हर हाल में समाप्त करे। ऐसा कोई कदम न उठाकर श्री मनमोहन सिंह ने भारत की भूमि उलटे बंगलादेश को सौंप दी। यह भारत राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। इससे भारत की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर धूमिल हुई है।

भाजपा महामंत्री श्री अनंत कुमार ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं से कहा कि संप्रग सरकार बाहरी तथा अंदरूनी मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो गई है। अब यह सरकार भारत जैसे बड़े देश की भूमि बंगलादेश को सौंपकर विश्व विरादरी को यह संदेश दे रही है कि भारत सरकार ने एक छोटे से देश के आगे घुटने टेक दिये। इससे आतंकवादियों के भी हौसले और बुलंद होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री विजोय चक्रवर्ती ने कहा कि वे स्वयं असम से आती हैं। इस समय असमवासी बंगलादेशी घुसपैठियों के दर्द से कराह रहे हैं लेकिन इस सरकार को अपने देशवासियों के हित की कोई भी चिंता नहीं है। राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल ने कहा कि समय आ गया है कि देशवासी मिलकर देश विरोधी संप्रग सरकार को सत्ता से हटायें क्योंकि इस सरकार को भारतवासियों से ज्यादा चिंता पड़ोसी मुल्कों के वाशिंदों से है।

प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि असम की भूमि बंगलादेश को सौंपकर संप्रग सरकार के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भारत का सिर दुनिया की नजरों में नीचा किया है। इसके लिए आने वाली पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा बंगलादेश को भूमि अंतरित किए जाने की सख्त विरोधी है। वह इस देश विरोधी सरकार से मांग करती है कि बंगलादेश को सौंपी गई भूमि तुरन्त वापस ली जाए। प्रधानमंत्री को चिकिन नेक भूमि की समस्याओं को बंगलादेश दौरे में सदैव के लिए निपटाने का प्रयास करना चाहिए था।

प्रधानमंत्री अपने बंगलादेश दौरे के दौरान बंगलादेश द्वारा हूजी को आतंकवादी संगठन घोषित कराने का समझौता करना चाहिए था ताकि बंगलादेश से भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो सकें। ■

उत्तर प्रदेश

पी.चिदम्बरम को बर्खास्त किया जाए : राजनाथ

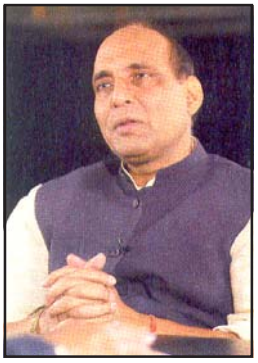

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गृहमंत्री एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को बर्खास्त किये जाने की मांग की है.

श्री सिंह 27 सितम्बर को सीसामऊ एवं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि टू जी स्पैक्ट्रम मामले में तिहाड जेल में बंद ए.राजा के यह कहने पर कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह तत्कालीन वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम के इशारे पर किया.

उन्होंने कहा कि इतना बडा सत्य उजागर होने के बाद भी प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष खामोश रहते हैं तो आने वाले समय में जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.

उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश दोनों ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं और यह संकट यूपीए सरकार ने पैदा किया है. उन्होंने कहा कि आज महंगाई से जनता त्राहि त्राहि कर रही है. इसके लिए वह कांग्रेस के अलावा सपा और बसपा को भी बराबर का दोषी मानते हैं क्योंकि इन दोनों ही दलों का केन्द्र को समर्थन प्राप्त है.

उत्तर प्रदेश में लड़ाई सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की : कलराज

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार, दुराचार एवं अनाचार की बढ़ती घटनाएं इशारा करती हैं कि राज्य में लड़ाई अब सत्ता परिवर्तन की नही बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की होगी।

सोनभद्र से विजय संकल्प सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मिश्र ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई है कि बच्चों के अपहरण दिन दहाड़े हत्याएं, छोटी–छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए पदचिह्नों को अपमानित करने की साजिश की जा रही है।

पीलीभीत के कटइयां गांव में गुरु ग्रंथ साहब को क्षति पहुंचाई गई लेकिन दोषियों की 48 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहुबलियों का साम्राज्य है। बसपा हुकूमत में अपराधी को जनसेवक की संज्ञा दी जाती है। मनरेगा में भयंकर भ्रष्टाचार है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में घोटाला चाहे केन्द्रीय योजना का धन हो या राज्य सरकार का सब में भ्रष्टाचार है।

झारखंड

सादगी के मिसाल थे पं. दीनदयाल जी : डा. गोस्वामी

रांची, 25 सितंबर (हि.स.) भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन त्याग, सादगी एवं बलिदान की मिसाल है। वे रविवार को प्रदेश मुख्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

श्री गोस्वामी ने कहा कि पंडित जी का जीवन बाल्यकाल से ही संघर्षपूर्ण रहा। विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो मुकाम हासिल किया वह कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। उनकी विद्वता, वाकपटुता एवं राष्ट्र के समग्र विकास के लिए समाज के सबसे पिछली पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के बारे में चिंता उनके व्यक्तित्व का आईना है।

कार्यक्रम में दीपक प्रकाश, राकेश प्रसाद, अनंत ओझा, प्रदीप सिन्हा, प्रदीप जायसवाल तथा मंजू देवी सहित अन्य उपस्थित थे। ■

‘सुशासन, विकास एवं स्वच्छ राजनीति’ होंगे रथयात्रा के उद्देश्य : लालकृष्ण आडवाणी

fo'k"k lokn nkrk }kjk

’ कात्ममानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितम्बर 2011 को डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित विशेषांक ‘राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास’ का विमोचन भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया। इस विशेषांक में राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास, आंतरिक सुरक्षा, अन्त्योदय सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के प्रख्यात बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और राजनीतिक नेताओं द्वारा लिखे गए लेख शामिल है।

इस विशेषांक विमोचन समारोह का उद्घाटन श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और कमल सन्देश के संपादक श्री प्रभात झा, न्यास के सचिव डॉ. नंद किशोर गर्ग, न्यास के कोषाध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल और भाजपा के साहित्य और प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अम्बा चरण वशिष्ठ ने दीप प्रज्जवलन कर किया। इस अवसर पर कमल संदेश संपादक मंडल के सदस्य सर्वश्री सत्यपाल, संजीव कुमार सिन्हा, राम प्रसाद त्रिपाठी, विकास आनंद, कला संपादक सर्वश्री धर्मेन्द्र कौशल एवं विकास सैनी तथा पत्रिका के प्रसार का काम देख रहे धर्मेश विद्यार्थी ने मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं पुस्तक से स्वागत किया।

> ***“मैं फिर से यात्रा पर जा रहा हूं। यात्रा का उद्देश्य न केवल सुशासन और विकास पर बल देना है बल्कि यह भी है कि आज कुशल प्रशासन और स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है। आज हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है।”***

‘कमल संदेश’ के हिन्दी एवं अंग्रेजी के दो विशेषांकों– ‘राष्ट्रवाद, सुशासन और स्वराज’ का विमोचन करते हुए कहा कि ये ऐसे विशेषांक हैं जिन्हें हर व्यक्ति को पढ़कर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे हर सही सोच वाले व्यक्ति में सृजनशीलता एवं सुविचार जागृत

होंगे।

श्री आडवाणी ने अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित पाक्षिक 'कमल संदेश' के संपादकीय मंडल की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इतना भव्य विशेषांक प्रकाशित कर पाठकों तक इतनी बौद्धिक सामग्री पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया है। उन्होंने श्रोताओं से सुविचारित पठन की आदत डालने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पहली कठिनाई तो अच्छे लेखकों की होती है। यदि अच्छे लेखक मिल जाते हैं तो अच्छे पाठकों की कमी महसूस होने लगती है जो ठीक ढंग से विचारों को समझ सकें और विश्लेषण कर पाएं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने भाषण में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता विषय पर उद्‌बोधित किया। उन्होंने बताया कि देश

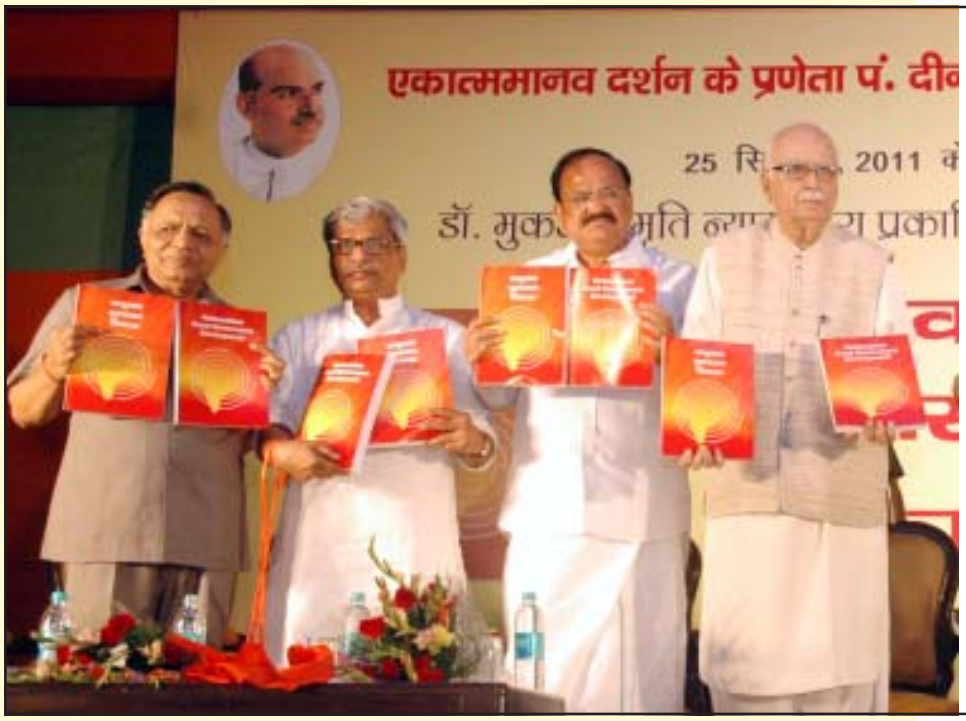

में तत्कालीन चल रहे 'दो निशान, दो विधान, दो प्रधान' की स्थिति के खिलाफ संघर्ष करते हुए राष्ट्रवाद के हित में किस प्रकार से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान किया था क्योंकि इस प्रकार की स्थिति विषमता के बीज बो रही थी और राष्ट्र को खण्ड–खण्ड कर रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि किस प्रकार से देश के पहले उप–प्रधानमंत्री लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों का भारत संघ में विलय

योगदान की भी चर्चा की।

इस अवसर पर, श्री आडवाणी ने भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दों पर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार की भी घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि ''मैं फिर से राष्ट्रहित में यात्रा की शुरूआत कर रहा हूं। मैं फिर से यात्रा पर जा रहा हूं। यात्रा का उद्देश्य न केवल सुशासन और विकास पर बल देना है बल्कि यह भी है कि आज कुशल प्रशासन और स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है। आज हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है। विदेशी बैंकों में विशाल परिमाण में काला धन भरा पड़ा है। इस बारे में तरह–तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं।''

न्यास के अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के शासन में राष्ट्रवाद की भावना पर चौतरफा हमले हो रहे हैं।

किया था और केवल एक रियासत जम्मू और कश्मीर ऐसी थी जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने श्री पटेल को जिम्मेदारी नहीं सौंपी और इसे स्वयं अपने हाथों में रखा और आज 64 वर्षों के बाद यही राज्य देश के लिए नासूर बन गया है।

श्री आडवाणी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 'एकात्म मानववाद' के माध्यम से किए गए उनके राष्ट्र निर्माण तथा 'अन्त्योदय' के माध्यम से निर्धनता–उन्मूलन के उनके महान

उन्होंने देश के विकास और राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए लोगों से सजग रहने का आह्वान किया। श्री नायडू ने कहा कि वर्तमान यूपीए सरकार सबसे खराब सरकार का उदाहरण है। सुशासन के लिए एक व्यापक परिवर्तन की जरूरत है और इसके लिए हमें जन–जागरण करना होगा।

मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और कमल संदेश के संपादक श्री प्रभात झा, सांसद ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सतत् प्रयासरत है। राष्ट्रवादी साहित्य के माध्यम से हम जनता के बीच राष्ट्रीय मुद्दों पर जन–जागरण कर रहे हैं।

अपने संबोधन में न्यास सचिव श्री नंद किशोर गर्ग ने कहा कि 'कमल सन्देश' की टीम सक्रियता से उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान हमने देश की समस्याओं और समाधान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर 'अन्त्योदय', '21वीं सदीः भारत की सदी', 'चुनौतियां', 'समाधान', 'संकल्प' और 'विकल्प' विशेषांक प्रकाशित कर पाठकों को श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि न्यास इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे भी करता रहेगा।

'कमल संदेश' के कार्यकारी संपादक डॉ. शिव शक्ति बक्सी ने 'राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास' विशेषांक के लेखकों व विषय–वस्तु के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारशील सामग्री प्रस्तुत की गई है।

भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सहसंयोजक श्री के. के. शर्मा को पूर्व में 'कमल संदेश' पत्रिका के संपादक मंडल सदस्य नाते किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए श्री लालकृष्ण आडवाणी ने शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल श्री केदार नाथ साहनी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा मुख्यालय प्रभारी प्रो. ओमप्रकाश कोहली, भाजपा मोर्चा/प्रकोष्ठ के समन्वयक श्री महेन्द्र पांडे, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री जगदीश मुखी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव सुश्री आरती मेहरा और सुश्री वाणी त्रिपाठी, दिल्ली की मेयर सुश्री रजनी अब्बी तथा सर्वश्री सुभाष कश्यप, जे.एस. राजपूत, सतपाल मल्लिक, अतुल कोठारी, आर.के. ओहरी, जे.पी. शर्मा सहित अनेक प्रख्यात लेखकगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ■